



डजिटल अर्थव्यवस्था: एक समताकारी अथवा आर्थिक असमता का स्रोत

भारत विश्व की डजिटल अर्थव्यवस्था में एक अग्रणी देश होगा ।

— सुंदर पचाई

डजिटल अर्थव्यवस्था, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु डजिटल प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग शामिल है, से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इससे **नवाचार, उत्पादकता और समावेशिता** की परिवर्तनकारी क्षमता प्राप्त होती है। यह धन सृजन के नए अवसर प्रदान करता है और सभी के लिये सूचना एवं बाजारों तक पहुँच को सुगम बनाता है कति इससे आर्थिक असमता भी बढ़ती है जो कचिती का वषिय है। डजिटल अर्थव्यवस्था का समताकारी होना अथवा आर्थिक असमता का स्रोत होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें **प्रौद्योगिकी, कौशल, नीतितगत मध्यवर्तन और बाजार की गतशीलता तक पहुँच** शामिल है।

डजिटल अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से, एक **प्रबल समकारक** के रूप में कार्य करने की क्षमता है। इससे **भौगोलिक अवस्थिति और भौतिक अवसंरचना** की आवश्यकता समाप्त होती है, जिससे व्यवसाय और व्यक्ती वस्तुतः किसी भी स्थान से वैश्विक बाजार में सक्रिय हो सकते हैं। बाजारों और सूचनाओं तक पहुँच को सभी के लिये सुलभ बनाने से विकासशील क्षेत्रों में लघु व्यवसायों और उद्यमियों को अपेक्षाकृत बड़ी, अधिक सुस्थिति कंपनियों के साथ प्रतस्पर्द्धा करने में सक्षम बनाता है, जिससे संबद्ध क्षेत्र में उनकी स्थिति में सुधार होता है। उदाहरण के लिये, Amazon, Alibaba और Etsy जैसे विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से लघु व्यवसायों को बाजार की परंपरागत बाधाओं को दूर करते हुए विश्व के ग्राहकों तक पहुँचने की सुविधा हुई है।

भारत के डजिटल पहचान कार्यक्रम, **आधार** और **यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)** से **वित्तीय सेवाओं** तक पहुँच में क्रांती आई है। आधार से लाखों भारतीयों के लिये बैंक खाते खोलने और सरकारी सेवाओं का अभिगम सुनिश्चित हुआ है, जबकि UPI से ग्रामीण क्षेत्रों में भी डजिटल भुगतान सहज और सुलभ हुआ है। **फ्लिपकार्ट** और **सैपडील** जैसी भारत की ई-कॉमर्स की प्रमुख कंपनियों की सहायता से लघु व्यवसायों के लिये देश के ग्राहक वर्ग तक पहुँच स्थापित करना संभव हुआ है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को बड़ी कंपनियों के साथ प्रतस्पर्द्धा करने के आवश्यक **साधन और बुनियादी ढाँचा** प्रदान करते हैं।

शिक्षा के डजिटल प्लेटफॉर्म जैसे विभिन्न डजिटल वेबसाइट और लर्निंग ऐप से शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और दूरवर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिये शिक्षा वहनीय और सुलभ हुई है। डजिटल शिक्षा उद्योग से समग्र देश में छात्रों की अवस्थिति से प्रभावित हुए बनिा उनके लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभिगम संभव हुआ है।

कई कंपनियों किसानों को प्रत्यक्ष रूप से बाजारों से जोड़ने, **मध्यस्थों को कम करने** और उनकी फसल के लिये बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिये डजिटल तकनीकों को प्रयोग में ला रही हैं। **ओपन नेटवर्क फॉर डजिटल कॉमर्स (ONDC)** सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य डजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिये छोटे खुदरा विक्रेताओं सहित सभी हतिधारकों के लिये एक वित्त नेटवर्क प्रदान करके **डजिटल वाणजिय को सभी के लिये सुलभ** बनाना है।

डजिटल प्लेटफॉर्म श्रम बाजार में समावेशिता को भी बढ़ावा देते हैं। अनेकों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से डजिटल कौशल वाले व्यक्तियों को उनकी अवस्थिति से प्रभावित हुए बनिा कार्य खोजना सरल हुआ है। इस सुविधा से विशेष रूप से विकासशील देशों के व्यक्ती लाभान्वित हुए हैं, जहाँ **उच्च बेरोज़गारी दर** और सीमिति स्थानीय अवसर मौजूद हैं। व्यक्तियों को किसी भी स्थान से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम बनाकर, डजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक गतशीलता के लिये नए अवसर सृजति करती है।

एक समताकारी के रूप में अपनी क्षमता के बावजूद, डजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक असमता को भी बढ़ा सकती है, विशेषकर जब डजिटल संसाधनों तक पहुँच असमान रूप से वितरित होती है। **"डजिटल विभाजन"**, उन लोगों के बीच का अंतराल है जिनके पास **इंटरनेट** और **डजिटल तकनीकों** तक पहुँच है एवं जिनके पास नहीं है, डजिटल अर्थव्यवस्था में असमता का प्रमुख कारक है। विश्व के अनेक भागों, विशेष रूप से ग्रामीण और **नमिन आय वाले क्षेत्रों** में, हाई-स्पीड इंटरनेट तक पहुँच सीमिति है। सीमिति पहुँच की यह कमी व्यक्तियों और व्यवसायों को **डजिटल अवसरों** का पूर्ण लाभ बाधति करती है और इस प्रकार मौजूदा आर्थिक असमताएँ और प्रबल होती हैं।

इसके अतिरिक्त, डजिटल अर्थव्यवस्था से कतपिय उद्योगों में वनिर-टेक्स-ऑल की स्थिति उत्पन्न हुई है। तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों जैसे- Google, Amazon, Facebook और Apple का अपने-अपने क्षेत्रों पर प्रभुत्व है और भारी मात्रा में धन और शक्ति अर्जति कर रही हैं। कुछ प्रमुख कंपनियों के बीच लाभ के इस संकेंद्रण से धनी और नरिधन का अंतराल और अधिक व्यपाक होता है। लघु कंपनियों और स्टार्टअप के लिये इन डजिटल कंपनियों के साथ प्रतस्पर्द्धा करना चुनौतीपूर्ण होता है, जिससे प्रतस्पर्द्धा कम हो जाती है और लघु व्यवसायियों की उन्नति के अवसर प्रभावित होते हैं।

असमता को बढ़ाने वाला एक और कारक **श्रम बाज़ार का ध्रुवीकरण** है। यद्यपि डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्रौद्योगिकी और **डेटा वजिज्ञान** में अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिये उच्च वेतन वाली नौकरियों सृजित होती हैं करती हैं कति इससे प्रायः ऐसे श्रमिक जो कम कुशल हैं, पीछे रह जाते हैं। **स्वचालन** और **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)** से विशेष रूप से वनिरिमाण, खुदरा और परिवहन में अनेक अल्प और मध्यम-कुशल नौकरियों परतस्थापति हो रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण हेतु आवश्यक कौशल के बिना श्रमिकों को बेरोज़गारी या अल्परोज़गार का सामना करना पड़ता है, जिससे आर्थिक असमता बढ़ती है।

इसके अतिरिक्त, डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता **गति इकॉनमी**, का श्रमिकों पर मलिा-जुला प्रभाव पड़ता है। यद्यपि **उबर** और **डोरडैश** इत्यादि जैसे गति प्लेटफॉर्म सुविधा अनुसार कार्य करने के अवसर प्रदान करते हैं कति इनमें प्रायः **अल्प वेतन**, **नौकरी की असुरक्षा** और **लाभों के अभाव** की समस्या होती है। इन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों, विशेष रूप से वकिसशील अर्थव्यवस्थाओं में, **कोशोषण** और **आर्थिक अस्थिरता का जोखिम** होता है, जिससे असमता और भी बढ़ जाती है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था का असमता के स्रोत के स्थान पर समताकारी स्रोत के रूप में इसकी भूमिका सुनिश्चित करने हेतु सरकारों और संस्थानों को लक्षति नीतगित मध्यवर्तन क्रियान्वति करने चाहिये। डिजिटल वभिाजन को कम करना अत्यावश्यक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये विशेष रूप से वंचति क्षेत्रों में **डिजिटल बुनियादी ढाँचे** में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें वहनीय हाई-स्पीड इंटरनेट तक पहुँच का वसितार करना, डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हाशियाई समुदाय डिजिटल अवसरों का लाभ उठाने के लिये आवश्यक उपकरण से सन्नद्ध हों।

इसके अतिरिक्त, प्रतसिपर्धी डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के प्रभुत्व को वनियमित करने के उद्देश्य से नीतियाँ वकिसति करना आवश्यक है। **निषिक्ष प्रतसिपर्द्धा** को बढ़ावा देने वाले नयिम **लघु व्यवसायों** और **स्टार्टअप** के लिये अधिक सम परविश तैयार करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, शोषण की रोकथाम करने और आर्थिक असमता को कम करने के लिये ऐसे **श्रम कानून** अधिनियमित करना आवश्यक है जनिमें **गति इकॉनमी श्रमिकों** की रक्षा, **उचित वेतन**, **नौकरी की सुरक्षा** और **उचित लाभ** का प्रावधान कया गया हो।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिये आवश्यक कौशल से श्रमिकों को लैस करने के लिये शैक्षिक सुधारों की भी आवश्यकता है। सरकारों को भवष्य की नौकरियों के लिये कार्यबल को तैयार करने के लिये विशेष रूप से प्रौद्योगिकी और डेटा वजिज्ञान से संबंधति क्षेत्रों में **STEM शक्षिा** एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्राथमकिता देनी चाहिये। तेज़ी से बदलते आर्थिक परदृश्य के अनुकूल श्रमिकों की मदद करने के लिये **आजीवन अधगम के कार्यक्रम** और **पुनः कौशल पहल** भी आवश्यक हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में **सभी के लिये सूचना, बाज़ार और अवसरों तक पहुँच को सुगम** बनाकर एक समताकारी के रूप में कार्य करने की वपिल क्षमता है। यद्यपि, **डिजिटल वभिाजन**, **बाज़ार संकेंद्रण** और **श्रम बाज़ार ध्रुवीकरण** को संबोधति करने के लिये सक्रयि उपायों के बिना, इससे आर्थिक असमता के बढ़ने का जोखिम है। **नीति नरिमाताओं**, **व्यवसायों** और **समाजों** के लिये वास्तवकि चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि **डिजिटल अर्थव्यवस्था** के लाभ व्यापक रूप से साझा किए जाएँ और इस डिजिटल परिवर्तन में सभी का समावेशन सुनिश्चित हो। लक्षति मध्यवर्तनों और समावेशी नीतियों के माध्यम से, डिजिटल अर्थव्यवस्था वभिाजन के स्रोत के स्थान पर समता का स्रोत बन सकती है।

डिजिटल परिवर्तन वर्तमान परदृश्य में व्यवसायों के समक्ष एक मूल यथार्थ है।

— वॉरेन बफेट